हिन्दी साप्ताहिक

RNI No. UPHIN/2011/43668

WWW.JANVEENA.COM

जनवीणा

स्वर जन-मन का...

वर्ष : 13 | अंक : 26 | लखनऊ, 14 जून, 2024 | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 3 रूपये

आसमान से बरसी आग, कानपुर रहा सबसे

गर्म आगरा में न्यूनतम तापमान 35 डिग्री

लखनऊ। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में लू का तीखा असर है। दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

पूरा प्रदेश प्रचंड गर्मी झेल रहा है। शुष्क व गर्म पछुआ हवा, आसमान साफ होने से सूर्य की तीखी धूप के कारण लू का दायरा तेजी से बढ़ा है। प्रदेश के 28 शहर लू की चपेट में रहे। गोरखपुर में तो तीव्र उष्ण लहर चली। 46.6 डिग्री सेल्सियस के साथ कानपुर प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान भी 34.9 डिग्री रहा, जो कि सर्वाधिक था।

आगरा में न्यूनतम तापमान ने बनाया रिकॉर्ड: आगरा के न्यूनतम तापमान ने रिकॉर्ड बनाया। बीते 50 वर्षों में तीसरी सबसे गर्म रात रही। यहां पर न्यूनतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के

मुताबिक, बीती रात 33.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आगरा के पिछले 50 वर्ष के प्रेक्षण इतिहास (1974-2024) में 34.8एष्ट-13 जून 2018 और 33.6एष्ट-05 जून 2017 के बाद जून महीने की तीसरी सबसे गर्म रात रही।

कल तक अभी कोई राहत

मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर जारी लू और भीषण लू की परिस्थितियां आगामी 15 जून तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के जारी रहेंगी। इसके बाद पूर्वी तराई क्षेत्र में हवा के पैटर्न में बदलाव होने और बादल छाने की संभावना है। बारिश के कारण पूर्वी तराई क्षेत्र में लू की स्थिति में 16 जून के बाद आंशिक कमी आने की संभावना है।

सर्वाधिक गर्म रहे ये शहर

कानपुर: 46.6, प्रयागराज: 46.4, आगरा : 46.5

इन शहरों में 45 पार रहा पारा: बुलंदशहर, अलीगढ़, हमीरपुर, उरई, फुरसतगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, बहराइच, वाराणसी, बाराबंकी

इन शहरों में रात का पारा 30 से 33.5 के बीच हुआ रिकॉर्ड: अलीगढ़, आगरा, इटावा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, झांसी, फतेहगढ़, प्रयागराज, बलिया, चुर्क, वाराणसी, लखनऊ, खीरी, कानपुर और हरदोई।

आज यहां तीव्र लू की चेतावनी

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास तीव्र लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

यहां ऑरेज अलट: प्रतापगढ़, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अंबेडकरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर आसपास के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ाई गईं, बच्चों के लिए 28 जून तक बंद रहेंगे विद्यालय

लखनऊ। यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं, बच्चों के लिए स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे।

यूपी में भीषण गर्मी को देखते हुए परिषदीय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक के लिए बढ़ा दी गई हैं। वहीं, बच्चों के लिए स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जानकारी दी है। बता दें कि भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने गर्मी की छुट्टियां बढ़ाने की मांग की थी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा था कि पूरा प्रदेश भीषण गर्मी व लू से तप रहा है। ऐसे में विद्यालयों को 18 जून से खोलना हितकर नहीं होगा। वहीं शिक्षकों की परस्पर तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। इसे देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां 30 जून तक की जाएं। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजे पत्र में कहा है कि वर्तमान में प्रदेश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाया जाए।

यूपी की राज्यपाल बोलीं, ट्रैफिक नियम का पालन न करने वालों से कराएं रक्तदान

लखनऊ। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर केजीएमयू में आयोजित कार्यक्रम में रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि अभी भी पर्याप्त मात्रा में रक्तदान नहीं हो रहा है। ऐसे में अलग तरीके अपनाए जाने चाहिए।

राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि जो युवा ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे रक्तदान कराया जा सकता है। वे शुक्रवार को केजीएमयू के ब्राउन हाल में आयोजित समारोह में बोल रही थीं। इस मौके पर उन्होंने रक्तदान और रक्तदान शिविर लगाने के लिए व्यक्ति और संस्थाओं को सम्मानित किया।

राज्यपाल ने कहा कि तमाम जागरूकता के बावजूद अभी भी पर्याप्त मात्रा में रक्तदान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इसके लिए नए तरीके तलाश करने होंगे। प्रदेश की जेलों में

रक्तदान शिविर लगाया जा सकता है। उनके अनुसार हर कानून तोड़ने पर सजा का प्रावधान नहीं है। सामान्य ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों से पुलिस रक्तदान करा सकती है। सामान्य मामलों में सजा के बजाय अस्पताल में सेवा और रक्तदान का निर्देश दिया जा सकता है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, केजीएमयू कुलपति प्रो सोनिया नित्यानंद, एनएचएम निदेशक पिंकी जोवेल और प्रति कुलपति अपजित कौर उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

नागरिक उठायें विश्व शांति के पक्ष में आवाज

मंगलवार को प्रकाशित हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट चिंताजनक है। इसके अनुसार हाल में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 56 संघर्ष हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पिछले लगभग 8 दशकों में इतनी अधिक अशांति कभी नहीं रही। यह रिपोर्ट आंकड़ों में प्रकाशित हुई है लेकिन ऐसी अशांति दुनिया को किस ओर ले जा रही है, यह बतलाने की जरूरत नहीं। इन संघर्षों के कारण होती तबाही से विकास पीछे रह जाता है। रिपोर्ट दुनिया भर में शांति बहाली के नये प्रयासों की जरूरत को भी दर्शाती है। संघर्षों में एक ओर देशों को अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेनाओं, गोला-बारूद आदि पर खर्च करना पड़ता है जिसके कारण नागरिकों की सुविधाओं में कटौतियां होती हैं। विस्थापन, मौतें, भुखमरी, बीमारियां, अशिक्षा आदि युद्धों का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, आवास व्यवस्थाएं या तो सीधी लड़ाइयों में बर्बाद होती हैं अथवा उन पर खर्च करना उन देशों की सरकारों के लिये कठिन हो जाता है जो संघर्षों में शामिल होते हैं। वैश्विक शांति के बिना मानव के विकास और उसकी गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह स्थिति सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11 करोड़ लोग लड़ाइयों के चलते विस्थापित हुए हैं या शरणार्थी शिविरों में जीवन जी रहे हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 92 देशों की सीमाओं पर या तो युद्ध जारी हैं अथवा वहां युद्ध सदृश्य परिस्थितियां हैं। 97 देशों में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज की गयी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के तीन चौथाई देशों ने रक्षा बजट में व्यापक बढ़ोतरी की है। वहां पिछले दो वर्षों से अशांति बनी हुई है। ऐसे ही, इजरायल के साथ फिलीस्तीन, ईरान आदि की लड़ाइयों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। हजारों लोग मारे गये हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इन युद्धों के कारण अधोरचना का विनाश सर्वाधिक होता है। सड़कें, पुल, स्कूल भवन, अस्पताल, आवासों को जो क्षति होती है वह नागरिकों का सीधा नुकसान है। युद्ध चलते तक पुनर्निर्माण सम्भव नहीं होता और युद्ध रूकने के बाद देशों को बदहाली से उबरने में वर्षों लग जाते हैं। युद्ध के कारण माली हालत जर्जर हो जाती है। इन देशों के नागरिकों को अपना जीवन बदहाली में काटना होता है। अशांति का असर किस प्रकार से लोगों के जीवन पर पड़ता है वह इस तथ्य के आधार पर आंका जा सकता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़ाइयों के कारण 19 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है जो दुनिया की जीडीपी का 13.5 फीसदी है- अमूनन प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये का नुकसान। इन स्थितियों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अक्सर माना जाता हैय और जो बड़े पैमाने पर सही भी है कि बड़े व शक्तिशाली देशों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का बस नहीं चलता। उपरोक्त उल्लिखित दोनों ही देशों में ऐसा होता दिखा है। यहां यह भी समझ लेना जरूरी है कि बहुत से शक्तिशाली देश हथियार उत्पादक भी हैं जिनकी दिलचस्पी शांति में कम युद्ध या तनाव की स्थिति को बनाये रखने में होती है। दुनिया में चाहे शीत युद्ध समाप्त हो गया हो और विश्व एकध्रुवीय बन गया हो तब भी किसी संघर्ष या युद्ध के दौरान देखा जाता है कि दुनिया दो धड़ों में विभाजित हो जाती है। कुछ देश लड़ाई में शामिल एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो कुछ दूसरे पक्ष के साथ। लड़ाई हो या न हो, परन्तु तनाव की यह स्थिति भी शक्तिशाली व हथियार निर्माता देशों के मुफीद होती है। लड़ने के लिये अथवा सुरक्षा के महेनजर उनके हथियार बिकते हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं तटस्थ देशों की शांति की अपीलों को अनसुना कर कई देश तनाव को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है वह कुछ सुकून भरी हो सकती है। पिछली रिपोर्ट के बाद भारत एवं उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की रैंकिंग सुधरी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरी दुनिया कहे जाने वाले एशियाई, अफ्रीकी व लातिन अमेरिका के अविकसित व विकासशील देशों को अशांति का खामियाजा अधिक भुगतना पड़ता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक तरह से निष्क्रिय हो जाने के बाद भारत की ओर से शांति की पहल होनी बन्द हो गयी है वरना इन परिस्थितियों में उसकी सुनी जाती थी। आंदोलन के पीछे महात्मा बुद्ध के पंचशील तथा महात्मा गांधी के अहिसा व शांति का संदेश होता था। आज भी इन दोनों के साथ जवाहरलाल नेहरू की बातें वैश्विक शांति के सन्दर्भ में प्रासंगिक बनी हुई हैं।

मोहन भागवत ने जो कहा और जो नहीं कहा

सर्वमित्रा सुरजन

एनडीए सरकार के गठन को जुम्मा-जुम्मा आठ दिन भी नहीं हुए कि अभी से इसमें बिखराव की खबरें आने लगीं हैं। तेदेपा और जदयू जैसे दलों के सहारे इस बार की एनडीए सरकार खड़ी हुई है। इसलिए इन दलों को मोदी की बैसाखी कहा जा रहा है। एक भी बैसाखी अलग हुई नहीं कि सरकार लड़खड़ा जाएगी या गिर जाएगी, यह राजनीति के जानकारों का कहना है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अतीत में एनडीए सरकार के साथ ऐसा हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी भी तीन बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन तीन में से दो बार उनकी सरकार गिर गयी थी, एक बार 13 दिन और एक बार 13 महीने में। केंद्र और राज्यों में कई उदाहरण मौजूद हैं, जब गठबंधन सहयोगियों के अचानक अलग हो जाने के कारण अच्छी-खासी चल रही सरकार गिर गई और सत्ताधारियों को विपक्ष में बैठना पड़ा। बिहार इसका ताजातरीन उदाहरण है, जहां नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका देकर भाजपा का साथ दे दिया। हरियाणा में भी ऐसा होने के कयास लग रहे थे, लेकिन वहां अब तक भाजपा की सरकार कायम है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब केन्द्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। वे संघ के दिनों के नरेन्द्र मोदी के साथी हैं, लिहाजा उन्हें यथोचित सम्मान मिल गया। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान को जब मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया, तो सवाल उठने लगे थे कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है। संघ की शाखाओं में दीक्षित शिवराज सिंह चौहान भारी मतों से जीत कर संसद पहुंचे और अब वे भी मंत्रिमंडल में सुशोभित कर दिए गए हैं। तीसरी बार भाजपा नेतृत्व में गठित एनडीए सरकार में संघ का क्या प्रभाव है, यह बात इन दो उदाहरणों से समझी जा सकती है। गठबंधन के साथी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी या रामदास अठावले इस प्रभाव से अनजान हों, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन्हें भी शायद अब तक इससे तकलीफनहीं है, क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए जो थोड़ा बहुत सामंजस्य बिठाना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, वे दोनों तरफसे किए जा रहे हैं। हालांकि कब तक आपसी समझदारी दिखाई जाती रहेगी, यह सवाल अब भी अनुत्तरित ही हैं। बहरहाल, सत्ता गठन के लिए किए गए समझौतों की इस पृष्ठभूमि में संघ के प्रभाव के साथ-साथ उसके उद्देश्यों को समझना कठिन नहीं है। हाल ही में कुछ ऐसे वाकये हुए हैं, जिनसे इस बात को थोड़े और खुलासे के साथ समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने चुनावों में जनता के समर्थन के लिए मंगलवार को आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि वे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से मोदी का परिवार का नारा हटा लें। गौरतलब है कि लालू प्रसाद ने जब परिवार के महत्व पर अपने भाषण में नरेन्द्र मोदी को घेरते हुए कहा था कि अपनी मां के देहांत के बाद भी उन्होंने बाल नहीं मुंडवाए थे, तो इसके जवाब में श्री मोदी ने पूरे भारत के लोगों को अपना परिवार बताया था और फिर भाजपा नेताओं समेत कई मोदी समर्थकों ने सोशल मीडिया में अपनी पहचान में मोदी का परिवार लिखना शुरु कर दिया था। अब नरेन्द्र मोदी उन्हें इस पहचान को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। यह काफी अजीब बात है कि कोई परिवार किसी मकसद के पूरा हो जाने के बाद खत्म करने के लिए कहा जाए। क्या सनातनी संस्कृति को मानने वाले इस बात से सहमत होंगे कि परिवार कांट्रैक्ट के आधार पर बने और फिर खत्म भी हो जाए। राजनीति में कुछ भी अकारथ नहीं होता, इसलिए नरेन्द्र मोदी की इस अपील के पीछे असल मकसद क्या है, यह शायद भविष्य में पता चले। एक अन्य आश्चर्य वाली बात यह है कि भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट में मार्गदर्शक मंडल विभाग में चार तस्वीरें हैं, जिनमें सबसे पहली तस्वीर नरेन्द्र मोदी की है, फिर लालकृष्ण आडवानी, मुरली मनोहर जोशी और फिर राजनाथ सिंह। 2014 में जब मार्गदर्शक मंडल बना था, तब भी नरेन्द्र मोदी और राजनाथ सिंह का नाम तो इनमें शामिल था, लेकिन इसका उल्लेख कभी नहीं किया जाता था। जिनकी आयु 75 पार की हो गई है, वे इसमें शामिल होंगे, यह सामान्य समझ थी। श्री मोदी अगले बरस 75 के होंगे और राजनाथ सिंह उनसे एक साल छोटे हैं। फिर इन दो नेताओं की तस्वीरें किसलिए भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शोभायमान हो रही हैं, यह भी चर्चा का विषय है। सरकार गठन और मोदी का परिवार खत्म होने की हलचलों के बीच एक महत्वपूर्ण घटना और घटी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में दिए एक भाषण में कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनके बाद यह कहा जाने लगा कि संघ और भाजपा के बीच दरार और बढ़ गई है। दरअसल मोहन भागवत ने मणिपुर में एक बरस से अधिक वक्त से जारी हिंसा का समाधान ढूंढने और शांति बहाली पर जोर दिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनसे आभास हुआ कि ये सब नरेन्द्र मोदी को नसीहत देने के लिए कहा गया है। जैसे, श्री भागवत ने कहा कि एक श्सेवकश् को अपने काम पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उसे असंबद्ध और अहंकार से रहित होना चाहिए। यहां राष्ट्रीय स्वयं सेवकों को नसीहत है या खुद को देश का प्रधानसेवक कहने वाले श्री मोदी को, यह स्पष्ट नहीं किया गया। फिर चुनाव परिणामों को सहजता से स्वीकार करके, उसके विश्लेषण के चक्कर में न पड़ने की राय देते हुए मोहन भागवत ने कहा कि चुनावों को श्युद्धश् की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। संघ हर चुनाव में जनमत को परिष्कृत करने का काम करता है और वह परिणामों के विश्लेषण में नहीं उलझता। संभवतरू मोहन भागवत का आशय यह था कि श्री मोदी कितने वोट से हार से बच गए और भाजपा की कहां, कितनी सीटें कम हुईं, या राम मंदिर का मुद्दा काम क्यों नहीं आया, हिंदुत्व की धार भोथरी क्यों पड़ी, इस पर माथापच्ची करने से बेहतर है कि संघ जिस तरह जनमत को परिष्कृत यानी जनता की मानसिकता को प्रभावित करने का काम उसे पूर्ववत करता रहे, बल्कि उसमें तेजी लाए, ताकि इस बार जो कसर रह गई, वो अगली बार पूरी हो जाए। ध्यान रहे कि अगले साल यानी 2025 में संघ की स्थापना के सौ बरस पूरे हो रहे हैं। जिस भारत को बनाने में संघ का कोई योगदान नहीं रहा, उसकी आजादी के 75 बरस को जब श्री मोदी ने राजनैतिक फायदे के लिए इतना भुनाया, वो भला संघ की शताब्दी के अवसर को सूखे में कैसे जाने दें। इसलिए अभी से संघ और नरेन्द्र मोदी इसकी तैयारी कर रहे हैं, यह मान ही लेना चाहिए। वैसे भी संघ इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा है। अक्टूबर 2022 में उप्र में संघ की चार दिन की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी, जिसमें संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने बताया था कि श्2024 के अंत तक देश के सभी मंडलों में शाखा पहुंचाने की योजना बनाई गई है, इसके अलावा संघ कार्य को लेकर समय देने के लिए देशभर में तीन हजार युवक शताब्दी विस्तारक के लिए निकल चुके हैं और एक हजार शताब्दी विस्तारक और निकलने वाले हैं। यह बात दो साल पहले की है, तो इसका मतलब कम से कम पांच-सात हजार विस्तारक यानी पूर्णकालिक प्रचारक की जगह अपने काम के साथ-साथ संघ का प्रचार करने वाले लोग देश भर में निकले होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हर घर अक्षत बांटने का काम ऐसे ही नहीं हुआ है।

रियासी आतंकी हमला दर्शाता है अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की सीमाएं

आशीष बिस्वास

सिख अलगाववादी अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से विजयी होने से से केंद्र सरकार असमंजस में है। भारत सरकार इस बात पर अनिर्णीत है कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं कि क्या उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जायेगा, जहां उन्हें रखा गया है, या अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है। जो भी स्पष्टीकरण हो, सरकार की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। न तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और न ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव में खालिस्तानी समर्थक के जीतने की संभावना पर विचार किया था। यहां तक कि एक नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नयी सरकार के गठन को देखते हुए एक नरम आधिकारिक प्रतिक्रिया भी राजनीतिक चर्चाओं को शांत करने में मदद कर सकती थी। सच तो यह है कि अमृतपाल सिंह की जीत ने भारत सरकार को चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नीति निर्माता नई दिल्ली में श्एनडीए गठबंधन्य स्थापित करने में व्यस्त थे। बदलाव मुश्किल नहीं था, लेकिन ध्यान बंटाया नहीं जा सकता था। नयी एनडीए सरकार को काम पर लगना था और भाजपा के वर्चस्व वाले प्रशासन के पास खालिस्तानी समर्थकों के लिए समय नहीं था। इसके अलावा, नयी सरकार को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के रियासी जिले में हिंदू तीर्थयात्रियों की आतंकवादी हत्या, जहां अभी-अभी चुनाव हुए थे,

उस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, एक स्पष्ट चेतावनी थी कि नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर नहीं थी। आतंकवादी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आतंकी हमले का समय सावधानी से चुना गया था। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन श्नयीय नरेंद्र मोदी सरकार की परीक्षा लेना चाहते थे। यह भारत के खिलाफ एक स्पष्ट रूप से भड़काऊ कार्रवाई थी। जब पुलवामा हुआ, तो मोदी ने जोरदार तरीके से बात की थी और नियंत्रण रेखा के पार बालाकोट पर विनाशकारी जवाबी हमले का आदेश दिया था। उस समय मोदी की पार्टी भाजपा के पास लोकसभा की 543सीटों में से 303 सीटें थीं। आज स्थिति अलग है। भाजपा ने 63 सीटें खो दी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उसके पास केवल 240 सीटें हैं। क्या मोदी 3.0 सीमा पार से उकसावे से निपटने की स्थिति में है?

रियासी आतंकी हमला एक अनूठी चुनौती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरी बार स्थापित मोदी सरकार को प्रतिक्रिया देने में इतना समय लग गया। रिकॉर्ड के लिए, यह केवल पाकिस्तान ही नहीं है, चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश भी यह जानना चाहेंगे कि नयी एनडीए सरकार विशिष्ट परेशानियों के खिलाफकैसे काम करती है। कांग्रेस ने रियासी की घटना की निंदा की है। लेकिन सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि क्या जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करना वाकई कारगर रहा? मोदी की कार्यशैली से परिचित अधिकांश पर्यवेक्षकों का मानना है कि भारत सरकार अपना समय और स्थान चुनकर प्रभावी ढंग से जवाब देगी।

रियासी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता स्थापित की जानी है। लेकिन खालिस्तानी भारत विरोधी आंदोलन को इसके समर्थन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो, अमृतपाल सिंह के साथ क्या किया जाना चाहिए? कनाडा या यू.के. में सिख अलगाववादियों की भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि - भारतीय मिशनों, सांस्कृतिक केंद्रों और मंदिरों को निशाना बनाना- एक क्षेत्रीय राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है जिसे बहुत पहले तैयार किया गया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इमरान खान शासन के दौरान कुछ साल पहले पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय सिख तीर्थयात्रियों की आवाजाही और उनके लिए पवित्र करतारपुर साहिब स्थल पर जाने की सुविधा के लिए उदारीकरण किया गया था, जो खालिस्तान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। कोलकाता के कुछ विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत सरकार को खालिस्तानी भारत विरोधी कूटनीतिक हमले के फिर से शुरू होने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह स्थान भारत की सीमा के बहुत करीब है, इसलिए भारत के लिए यह सुविधाजनक स्थिति नहीं है। सिखों के लिए नियमों में ढील दिए जाने से खालिस्तानी समर्थक तत्वों सहित भारतीय सिखों की संख्या में वृद्धि हुई है। केनेडा और अन्य जगहों पर भारत सरकार भारतीय राजनयिकों के सामने आने वाली चुनौतियों ने पहले व्यक्त की गयी आशंकाओं की पुष्टि की है। वास्तव में ब्रिटेन, केनेडा या अमेरिकी राजनयिकों के एक वर्ग में खालिस्तानियों के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन भारत के लिए एक रहस्योद्घाटन, एक दर्दनाक सीखने के अनुभव से कम नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत के लिए अपने सभी दिखावटी समर्थन के बावजूद, पश्चिम ने भारतीय राजनीतिक संस्थानों, इसकी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, इसके आम चुनावों, इसके मानव संसाधन रिकॉर्ड और अल्पसंख्यकों को संभालने के बारे में अपना अविश्वास व्यक्त करना कभी बंद नहीं किया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा किसानों के आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों और भाजपा की ताकत में उल्लेखनीय गिरावट को लेकर पश्चिमी मीडिया के बड़े हिस्से के बीच आम तौर पर संतुष्ट स्वर में कोई गलती नहीं हो सकती है। स्पष्ट रूप से, भारत एशिया में एक क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन यह भारतीय नेताओं या उनके राजनीतिक दलों के लिए उन्नत पश्चिम के मुकाबले अहंकारी होने के लिए ठीक नहीं होगा!

एनडीए को इस मामले में सावधानी से कदम उठाना चाहिए। वर्तमान स्थिति में, शत्रुतापूर्ण चीन और अविश्वासी पश्चिमी देशों के समूह का सामना करते हुए, उसे अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए काम तय है। खालिस्तानियों द्वारा पेश की गयी चुनौती से सावधानीपूर्वक निपटना होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अमृतपाल सिंह ने अपने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी पर लगभग 2,00,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, जो पंजाब में सबसे अधिक है। इसके अलावा, सिंह संसदीय चुनाव जीतने वाले एकमात्र अलगाववादी नहीं हैं। इंजीनियर राशिद, एक अन्य अलगाववादी, ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और जीता। अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद में जो बात समान है, वह यह है कि दोनों का भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं है।

पारदर्शिता-शुचिता के प्रश्न

हाल के दिनों में देश में विभिन्न रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने और संदेह के घेरे में आने के मामले लगातार उजागर होते रहे हैं। निश्चित रूप से सुनहरे भविष्य की आस में रात-दिन एक करने वाले प्रतियोगियों के साथ यह अन्याय बेहद कष्टदायक है। जो प्रतिभागियों का विश्वास व्यवस्था से उठाता है। मेडिकल परीक्षा की पुरानी प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिये लाई गई नई व्यवस्था भी अब सवालों के घेरे में है। यही वजह है वर्ष 2024 की नीट-यूजी परीक्षा के रिजल्ट आने पर परीक्षार्थियों में गहरा रोष व्याप्त हो गया। जिसके खिलाफ हजारों छात्रों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। छात्र दोबारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। बीते सोमवार इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस देकर जवाब देने को कहा है। दरअसल, परीक्षार्थी पेपर लीक व नंबर देने में अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि इस अविश्वास पैदा होने की वजह क्या है? जाहिरा तौर पर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा प्रणाली को संदेह से परे होना ही चाहिए। यदि व्यवस्था में कोई खामी है तो उसका निराकरण बेहद जरूरी है। दरअसल, इस संदेह की वजह यह भी है कि देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिये एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा यानी नीट-यूजी को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। आरोप लगे हैं कि इस बार परीक्षा में 67 कैंडिडेट को शत-प्रतिशत अंक मिले हैं, जबकि पिछले पांच वर्षों में पूर्ण अंक पाने वालों की संख्या सिर्फतीन थी। सवाल ग्रेस मार्क्स देने की तार्किकता को लेकर भी उठे हैं। वहीं टॉप पर आने वाले 67 छात्र चुनिंदा कोचिंग सेंटरों से जुड़े हैं। कुल मिलाकर परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। निश्चित रूप से लाखों छात्रों की उम्मीदों वाली इस देशव्यापी परीक्षा को लेकर किसी किंतु-परंतु की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। दरअसल, देश के विभिन्न राज्य भी इस परीक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। खासकर कोचिंग सेंटरों के खेल व अंग्रेजी के वर्चस्व के चलते आरोप लगाये जाते हैं। आरोप हैं कि इस परीक्षा में हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों को न्याय नहीं मिलता। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई राज्य आरोप लगाते रहे हैं कि राज्य की भाषा के छात्रों को नई परीक्षा प्रणाली से नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने बाकायदा इस बाबत पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित की थी। राज्य सरकार का आरोप है कि मेडिकल कॉलेजों में तमिल भाषी छात्रों को कम जगह मिल रही है। निश्चित रूप से जहां इस परीक्षा के पेपर लीक व ग्रेस मार्क्स में अनियमितताओं को लेकर उठे सवालों के समाधान तलाशने की जरूरत है, वहीं हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के परीक्षार्थियों के साथ न्याय होना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब पूरे देश में हजारों छात्र पुनरू परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं और पूरे देश में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की जा रही हैं तो नीति-नियंताओं को मामले की तह तक जाना चाहिए। गत पांच मई को हुई इस परीक्षा में चौबीस लाख परीक्षार्थी शामिल होने की बात कही जा रही है।

तो इसके व्यापक दायरे और इससे जुड़ी आकांक्षाओं का आकलन सहज ही हो जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को शत-प्रतिशत अंक मिलने तथा पंद्रह सौ छात्रों का अनुग्रह अंक पा जाना तार्किकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। निस्संदेह, लाखों छात्रों के लिये परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था संदेह से मुक्त होनी चाहिए। परीक्षा की शुचिता बनाये रखने के लिये निष्पक्ष जांच जरूरी है। अन्यथा छात्रों का व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि इन्हीं अव्यवस्था व अनियमितताओं के चलते हर साल लाखों छात्र पढ़ाई व नौकरी के लिये लगातार विदेश जा रहे हैं। भारतीय प्रतिभाओं व धन का बाहर जाना देश के हित में कदापि नहीं हो सकता है।

संस्कृति नीति बनाने की तैयारी, ड्राफ्ट तैयार, 1500 ग्राम सभाओं को वाद्ययंत्र वितरित

लोक कलाकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं: जयवीर

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने कहा है कि प्रदेश की लोक संगीत हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर है। लोक संगीत एवं कलाकारों को संरक्षित करना जरूरी है। लोक संगीत को संरक्षण देने की उदासीनता के कारण ही बहुत-सी लोक कलाएं एवं संगीत विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी हैं। गत वर्ष कलाकारों के मानदेय भुगतान में काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए एक जांच कमेटी कठित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलाकारों का शोषण और उत्पीड़न बर्दास्त नहीं किया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत कलाकार को साल में तीन कार्यक्रम आवंटित किये जायेंगे। कार्यक्रम से पूर्व उनके पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत अग्रिम तथा शेष धनराशि कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद सीधे उनके खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। प्रदेश की कोई सुव्यवस्थित संस्कृति नीति नहीं थी। लोक कलाओं तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा समृद्ध विरासत को बचाये रखने के लिए संस्कृति नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। विभिन्न संस्थाओं के विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त किये गये हैं। प्रदेश के संस्कृति विभाग लोक कलाओं को संरक्षण देने तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए एक कारगर कार्ययोजना एक सप्ताह के अंदर बनाये जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की संस्कृति का अमिट संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दे रही है। लोक संगीत तथा इससे जुड़े कलाकारों को रोजी-रोटी की व्यवस्था के लिए अब तक 1500 ग्राम सभाओं को वाद्ययंत्र के सेट वितरित किए गए हैं। अवशेष ग्राम सभाओं को भी इस योजना से आच्छादित किया जायेगा। मंत्री जयवीर सिंह ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा युवाओं को जोड़ने के लिए देशभर की प्रतिष्ठित संस्थाओं से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापनों की समीक्षा करते हुए कहा कि समझौता ज्ञापन का परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए। समझौते की विभिन्न गतिविधियां लगातार चलनी चाहिए। वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया जाना चाहिए। समझौता ज्ञापनों की अब तक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।पर्यटन मंत्री ने संस्कृति विभाग के अधीन आने वाली सभी संस्थाओं तथा अकादमियों का बिन्दुवार समीक्षा की, उन्होंने निर्देश दिए कि खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। इसके साथ ही संस्थान अपने माध्यम से ऐसे नवाचार तथा गतिविधियों पर जोर दें, जिससे उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें। उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटकों के आवक में प्रदेश पहले स्थान पर है। एक पर्यटक छः लोगों को रोजगार देता है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसको देखते हुए सभी अकादमी एवं संस्थान पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा दें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के समय उत्तर प्रदेश संस्कृति प्रोत्साहन परिषद के नामित सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि हर संस्थान और अकादमी के भवन एवं अन्य निर्माण भव्य और दिव्य दिखाई दे इसके लिए भी कार्ययोजना तैयार की जाए। पर्यटन मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मूर्ति निर्माण की अद्यतन स्थिति की भी गहन समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि 34 में से 22 मूर्तियां अब तक तैयार की गई हैं। शेष पर कार्य प्रगति पर है। पृथ्वीराज चौहान, भारत रत्न अटल विहारी वाजपेयी, डॉ भीमराव अम्बेडकर, महर्षि वाल्मिकी तथा महाराजा दक्ष प्रजापति की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। इसके अलावा पं दीनदयाल उपाध्याय, महायोगी गोरख नाथ, महाराणा प्रताप, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तैयार हो गई है। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन योजनाओं, कार्ययोजनाओं के ड्राफ्ट, भवनों के सौंदर्यीकरण का कार्य मंत्री के निर्देशों के अनुरूप पूरा किया जाए।

स्वयं सहायता समूहों को दिया जा रहा है भरपूर प्रोत्साहनः केशव मौर्य

लखनऊ (यूएनएस)। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों व क्रियाकलापों को बढ़ावा देने व उन्हें प्रोत्साहित करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे स्वयं सहायता समूहों की आमदनी में और अधिक इजाफ हो सके तथा ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी होने के साथ अपने परिवार को आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से समृद्ध व सक्षम बना सकें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवॉल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि बढ़ाये जाने से न केवल समूहों के क्रियाकलापों की गति तेज होगी, बल्कि समूहों की दीदियों का समाज में सम्मान बढ़ेगा। स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 मे सभी योग्य स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड के अंतर्गत 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार तथा सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत 1 लाख 10 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रूपये कर दिया गया है। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने बताया कि इसका अनुमोदन विगत दिनों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश स्तर की 20वीं शासी निकाय की बैठक में प्रदान किया जा चुका है। इस संबंध में निर्धारित शर्तों व भारत सरकार की गाइड लाइन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की जाने वाली रिवॉल्विंग फण्ड व सामुदायिक निवेश निधि को बढ़ाये जाने के संबंध में मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दीपा रंजन द्वारा जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर गाइड लाइन्स के अनुपालन की अपेक्षा की गई है। मिशन निदेशक दीपा रंजन ने जिला अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि आरएफव सीआईएफपात्र समूह की लोन कमेटी मीटिंग करवाने के उपरान्त फण्ड डिस्बर्समेन्ट माड्यूल के माध्यम से मांग किया जायेगा। समूहों का खाता सत्यापन करवाकर शर्तों व नियमों का पालन करते हुए फण्ड निर्गत किया जाना है। उन्हीं समूहों को रिवाल्विंग फण्ड जारी किया जायेगा, जो तीन माह की अवधि पूर्ण कर चुके हों, समूह द्वारा पंच सूत्र का मिलन किया जा रहा हो।

सिंचाई विभाग ने पुनर्जीवित की छोटी गण्डक नदी-स्वतंत्र देव

लखनऊ (यूएनएस)। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा गुर्रा नदी के ढाल को कम करके ग्रीष्म ऋतु में रामी नदी में निरन्तर प्रवाह बनाकर गोरखपुर के 27 ग्राम तथा देवरिया के 06 ग्रामों सहित कुल 33 ग्रामों की लगभग 60000 की आबादी तथा पशु, पक्षियों को लाभान्वित करने के साथ भू-गर्भ जल को भी बढ़ाने का कार्य किया है। वहीं इसके साथ ही गुर्रा नदी से बाढ़ के समय बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करके गोरखपुर के 20 ग्राम एवं देवरिया के 06 ग्रामों सहित कुल 26 ग्रामों की 35000 आबादी को सुरक्षित करने के सराहनीय कार्य किया गया है। गुर्रा नदी का उद्गम स्थल गोरखपुर में प्रवाहित रामी नदी से ग्राम-रूदाइन मझगंवा, तहसील-बाँसगांव एवं ग्राम सेमरौना, तहसील-चौरी चौरा है। उद्गम स्थल से गुर्रा नदी का ढाल रामी नदी के ढाल से अधिक होने के कारण बाढ़ एवं ग्रीष्म ऋतु में पानी का बहाव समानुपातिक नहीं होने से बाढ़ अवधि में गुर्रा नदी से भारी तबाही की सम्भावना बनी रहती थी, वहीं दूसरी ओर ग्रीष्म ऋतु में रामी नदी के सूख जाने के कारण आबादी एवं पशु पक्षियों एवं जीव-जन्तुओं को कृषि कार्य एवं पीने का पानी नहीं मिलने से जन-जीवन प्रभावित होता था। इसके साथ ही सिंचाई विभाग की पहल पर छोटी गंडक नदी को भी पुनर्जीवित करने हेतु प्रयास किये गये, जिसके क्रम में नदी के सेक्शन की पुनर्स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया है। नदी को मूल स्वरूप में लाने की प्रक्रिया के दौरान ही भूजल स्तर नदी में आने लगा और सिंचाई विभाग द्वारा की गई पहल कारगर व सफल साबित हुई। छोटी गण्डक एक घुमावदार भूजल आधारित नदी है जो नेपाल राष्ट्र के परसौनी जनपद-नवलपरासी से उद्गमित होकर भारत राष्ट्र में लक्ष्मीपुर खुर्द ग्राम सभा जनपद-महराजगंज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।

नागरिक सुरक्षा के कार्यों को जनता के बीच ले जायें:प्रजापति

नागरिक सुरक्षा के रिक्त पद भरने के निर्देश, होमगार्ड जवानों को मिले अधिकतम ड्यूटी

लखनऊ (यूएनएस)। प्रदेश के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने आज नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा की। बैठक में नागरिक सुरक्षा के कार्यों को जनोपयोगी ढंग से उपयोग में लाये जाने हेतु उपस्थित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि जिलाधिकारियों के माध्यम से जनपदों में नागरिक सुरक्षा के वालंटियर्स को जन कार्यों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जाय साथ ही समय-समय पर उनके कार्यों की समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा के वालंटियर्स के जनहित के कार्यों से आम जनता को अवगत कराने हेतु समुचित प्रयास किये जायें जिससे जनता में नागरिक सुरक्षा के कार्यों के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो। श्री प्रजापति ने होमगार्ड सेवा को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने हेतु सार्थक प्रयास किये जाने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि होमगार्ड्स को अधिकतम ड्यूटी आवंटित किये जाने हेतु नियमानुसार रोस्टर का निर्धारण कर उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।श्री प्रजापति ने नागरिक सुरक्षा विभाग एवं होमगार्ड विभाग को समृद्ध व सुदृढ़ बनाये जाने पर विभागीय अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक 15 जनपदों में नागरिक सुरक्षा की इकाई कार्य कर रही है तथा शेष 60 जनपदों में नागरिक सुरक्षा के वालंटियर्स तैनात किये जाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। इस पर मा0 मंत्री जी ने कहा कि शासन भेजे गये प्रस्ताव को व्यक्तिगत सम्पर्क कर शीघ्र अनुमोदित कराया जाए और साथ ही विभाग के कार्यों यथा प्राकृतिक आपदा, आकस्मिक घटनायें, स्थानीय आयोजनों के साथ ही विभागों के जिला स्तरीय कार्यों आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु पर्याप्त धन की उपलब्धता की गणना करते हुए बजट का पुनरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि बख्शी का तालाब स्थित विभागीय ट्रेनिंग सेंटर को और अधिक विकसित तथा क्रियाशील किये जाने हेतु यथा आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराया जाय।

शिवपाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊ (यूएनएस)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीयअध्यक्ष अखिलेश यादव चाचा शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के मूड में आ गए हैं। वे खुद राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन के अहम किरदार हैं।

सपा ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन उनकी अगुवाई में रहा है, उसके हर सियासी जानकार कायल है। अब उनकी केंद्रीय सियासत में एंट्री हो गई है। पहले भी वे सांसद रहे हैं लेकिन आज के हालात पहले अलग है। अब वे विधानसभा की सदस्यता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अनुभवी विधायक को सौंपनी हैं। शिवपाल यादव के इर्दगिर्द सुई घूम रही हैं।अखिलेश यादव के चाचा और जसवंतनगर विधानसभा से 6 बार विधायक चुने गए शिवपाल सिंह यादव को नेता प्रतिपक्ष का कमान सौंपी जा सकती है। उनके पास इसका अनुभव भी है और पार्टी संगठन में जबरदस्त पकड़ भी है। यही नहीं 2009 में शिवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल भी चुके हैं। जो उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखता है। उनके पास सरकार और संगठन दोनों का लंबा अनुभव है।अखिलेश यादव शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक तीर से कई निशाने साधने की भी कोशिश में हैं। शिवपाल को लेकर बार-बार नाराज होने की खबर चलती है जिसे लेकर सीएम योगी और बीजेपी लगातार तंज कसते रहते हैं। ऐसे में वह शिवपाल यादव को यह पद देकर ये संदेश देने चाहेंगे कि, चाचा-भतीजे के बीच को मतभेद नहीं हैं। इसके अलावा सदन में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता के सामने एक मझा हुआ राजनीतिज्ञ चाहिए, जिसके लिए शिवपाल एक दम फिट हैं।

भाजपा मात्र भगवान श्रीराम के नाम का इस्तेमाल सत्ता प्राप्ति के लिये करती है: प्रमोद तिवारी

लखनऊ (यूएनएस)। प्रमोद तिवारी, सांसद, उप नेता, राज्य सभा ने कहा है कि जगतगुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानन्द सरस्वती ने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनतापार्टी ने हिन्दुओं की धर्मस्थली एवं पवित्र स्थली को भोग स्थली बना दिया, उसी का परिणाम है कि अयोध्या में उसकी हार हुई है।

भा.ज.पा. भगवान श्रीराम के नाम का सहारा लेकर हिन्दुओं की भावनाओं और उनकी आस्था का इस्तेमाल अपनी सत्ता लोलुपता के लिये करती है। श्री तिवारी ने कहा है कि पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वती के बयान से पूरी तरह तस्वीर साफ हो गयी है कि भा.ज.पा. मात्र भगवान श्रीराम के नाम का इस्तेमाल अपनी सत्ता प्राप्ति के लिये करती है, उसके लिये भगवान श्रीराम आस्था के नाम नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति के साधन मात्र है। भारतीय जनतापार्टी ने भगवान श्रीराम के जन्म स्थान अयोध्या की पवित्रता को नष्ट किया है-भारतीय जनतापार्टी ने अयोध्या को तपस्थली तथा आस्था का केन्द्र नहीं बल्कि पर्यटन का केन्द्र बनाकर धन कमाने का एक साधन बनाया जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अयोध्या में भारतीय जनतापार्टी का सफाया हो गया। श्री तिवारी ने कहा है कि यही हाल प्रमुख धार्मिक स्थली काशी में किया गया है उसकी पवित्रता पर ध्यान न देकर पर्यटन से पैसा कैसे कमाया जाय ? इस पर ध्यान दिया गया है। इस तरह माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने अयोध्या और काशी जैसी हिन्दुओं की आस्था के प्रमुख स्थान की पवित्रता को नष्ट किया है।

जगतगुरु शंकराचार्य जी का यह एक संदेश है जिस पर लोगों को, विशेषरूप से मोदी और योगी सहित भा.ज.पा. वालों को समझना चाहिए। तपस्थली की पवित्रता यदि नष्ट किया जायेगा और उसे भोगस्थली बनाया जायेगा तो इसका परिणाम यही होगा। श्री तिवारी ने कहा है कि जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती के संदेश पर गौर करने की बात है कि अयोध्या से लेकर भगवान श्रीराम के चरण कमल जहाँ पड़े, पूरे ''राम गमन मार्ग'' पर- अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुलतानपुर, प्रतापगढ़ कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, रामटेक, नासिक, सबरी स्थली और रामेश्वरम आदि जहाँ- जहाँ होकर प्रभू श्रीराम गये- वहाँ- वहाँ भारतीय जनतापार्टी का सफाया हो गया। धर्म का इस्तेमाल कभी राजनैतिक लाभ के लिये नहीं होना चाहिए अन्यथा एक न एक दिन उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है, जैसे भा.ज.पा. ने सत्ता प्राप्त करने के लिये भगवान श्रीराम के नाम का सहारा लेकर हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, किन्तु उसका असली चेहरा आज जनता के सामने उजागर हो गया है कि भगवान श्रीराम की जन्म स्थली अयोध्या ही नहीं बल्कि जहाँ-जहाँ होकर भगवान श्रीराम गये वहाँ-वहाँ भा.ज.पा. प्रत्याशी को पराजय का स्वाद चखना पड़ा है ।

कांग्रेस का प्रदर्शन, नीट परीक्षा में धांधली का आरोप

अमेठी (यूएनएस)। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा में एक ही सेंटर के कई टॉपर निकलने के बाद धांधली का आरोप लगाकर सपा के बाद अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। आज बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की मांग की। चार जून को मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली नीट परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। रिजल्ट होने के बाद एक ही सेंटर के कई छात्र टॉपर निकले जिसके बाद परीक्षा में धांधली का आरोप लगने लगा। आज यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कलक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने कहा कि नीट में भ्रष्टाचार हुआ है। जो परिणाम आए हैं वो चौकाने वाले हैं और देश के 24 लाख नीट परीक्षार्थियों की जिंदगी खतरे में है। अमेठी का यूथ कांग्रेस परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफहै। हमारे देश के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किसी को नहीं करने दिया जाएगा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को दिया गया है। हमारी मांग है की परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जाए।

कांग्रेस की जीत के बाद उत्साह

अमेठी (यूएनएस)। अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा ने चुनाव जीतने के बाद लगातार लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में कार्यकर्ता आभार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज अमेठी कांग्रेस कार्यालय मे सांसद किशोरी लाल शर्मा की जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आभार समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस संगठन के विधान सभा अमेठी के भादर, भेटुआ, संग्रामपुर व अमेठी ब्लॉक के ग्राम पंचायत अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष वरिष्ठ पदाधिकारियो व इंडिया गठबंधन दल के नेताओं ने भी गर्म जोशी से अपने सांसद का अभिनन्दन किया।

दीक्षा तिवारी की मौत में नया मोड़, छत पर मिले घसीटने के निशान

कानपुर। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के परीक्षा भवन की पांचवीं मंजिल में दो दोस्तों के साथ बैठी डॉक्टर दीक्षा तिवारी (26) की नीचे गिरने से मौत हो गई। 2023 में एमबीबीएस करने के बाद तीनों की इसी साल इंटर्नशिप पूरी हुई थी। इसके बाद तीनों का ही अलग-अलग अस्पतालों में मेडिकल अफसर पद पर चयन हो गया था। इसी खुशी में तीनों ने बुधवार रात को एक दोस्त के कमरे में पार्टी की और इसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। पांचवीं मंजिल पर बने डक्ट के स्लैब में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक स्लैब धंसने से डॉ. दीक्षा नीचे जा गिरी। हालांकि बरेली से आए परिजनों ने दोनों दोस्तों पर ही नीचे फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम ने बताया कि बरेली की रहने वाली डॉ. दीक्षा तिवारी और कल्याणपुर के रहने वाले उसके सहपाठी डॉ. मयंक सिंह का मेरठ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल अफसर पद पर चयन हुआ था। तीसरे दोस्त मुजफ्फरनगर के डॉ. हिमांशु कुमार का कानपुर मेडिकल कॉलेज में इसी पद पर चयन हुआ था। इस खुशी में डॉ. दीक्षा ने पार्टी दी थी। तीनों ने पहले बुधवार रात आर्यनगर स्थित डॉ. हिमांशु के कमरे में पार्टी की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज स्थित परीक्षा भवन की पांचवीं मंजिल पर पहुंच गए। डक्ट के ऊपर बने स्लैब पर बैठकर बातचीत कर रहे थे।

तभी अचानक स्लैब धंस गया और डॉ. दीक्षा नीचे जा गिरी। दोनों साथी उसे लेकर हैलट पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। स्वरूपनगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों और अधिकारियों को सूचना दी। एडिशनल सीपी हरीश चंदर, डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम की मानें तो दीक्षा जिस डक्ट पर बैठी थी, वह बेहद कमजोर थी। इस वजह से हादसा हो गया। वहीं हादसे की सूचना पर शहर आए दीक्षा के चचेरे भाई गौरव ने आरोप लगाया कि छत पर रगड़ के निशान मिले हैं, जिससे लग रहा है कि दीक्षा को घसीटकर डक्ट से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने इस आरोप के बाद डॉ. मयंक और डॉ. हिमांशु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है।

चचेरे भाई गौरव ने बताया कि उसकी बहन दीक्षा की मौत की जो कहानी सुनाई गई है, वो ठीक नहीं लग रही है। छत पर पैरों के घसीटने के निशान हैं। मेरी बहन पैरों में चप्पल के साथ नीचे गिरी है। संदेह है कि साथी डॉक्टरों ने उसे डक्ट में धक्का दिया है। बरेली से आए दीक्षा के मौसा अरुण दुबे का आरोप था कि फॉरेंसिक टीम ने ठीक से जांच नहीं की। छत पर पैरों के घसीटने के निशान बने हुए हैं, उसे पुलिस ने नजरअंदाज किया। मूलरूप से इटावा के जसवंतनगर अजनौरा गांव की रहने वाली डॉ. दीक्षा तिवारी के पिता प्रदीप तिवारी का बरेली में प्रिंटिंग प्रेस का काम है। इसके चलते वे कई साल से बरेली के सुरेश शर्मा नगर में रहते हैं। शहर आए प्रदीप तिवारी ने बताया कि परिवार में पत्नी रेनू उर्फ अनीता, बेटा मयंक और बेटी दीक्षा थी। मयंक पुणे में इंजीनियर है। वर्ष 2018 में दीक्षा का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हुआ था।

2023 में एमबीबीएस हुआ और 2024 में इंटर्नशिप पूरी की। इसके बाद उसे मेरठ में नौकरी मिल गई। दो दिन पहले ही वे बेटी को लेकर दस्तावेज का सत्यापन कराने मेरठ गए थे।

25 जून का दीक्षा की जॉइनिंग थी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद वह बरेली चले गए, जबकि दीक्षा 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा में शामिल होने के लिए कानपुर आ गई थी। आरएस गौतम, डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि मौके पर जाकर जांच की गई है। प्रथम दृष्टया डॉक्टर की मौत हादसा लग रही है। परिजनों की तहरीर, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथी डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है।

सोलर पावर प्लांट से बिजली पैदा कर निगम बचाएगा सालाना 60 करोड़

कानपुर। किशनपुर गांव में 25 मेगावाट का सोलर प्लांट म्यूनिसिपल बांड से प्राप्त होने वाले 100 करोड़ रुपये से स्थापित कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता की वजह से यह कार्य रुक गया था। कानपुर नगर निगम किशनपुर गांव में 25 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करेगा। नगर आयुक्त ने इसके लिए यूपीनेडा के अधिकारियों से संपर्क साधा है। नगर निगम का दावा है कि प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की बदौलत हर महीने करीब पांच करोड़ और सालना 60 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसे विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा। प्लांट स्थापना के लिए आईआईटी कंसलटेंसी देगा। फिलहाल निगम को यूपीनेडा के जवाब का इंतजार है। बता दें, नगर निगम सदन की 19 फरवरी को हुई बैठक में बिजली बचाने के उद्देश्य से 25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। इस प्लांट के लिए ग्राम किशनपुर स्थित चकेरी सीवेज फार्म की जमीन पर 60 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन वहां बने कान्हा उपवन के पीछे है। अधिकारियों का कहना है कि प्लांट को स्थापित करने में आने वाला खर्च म्यूनिसिपल बांड से प्राप्त होने वाले 100 करोड़ रुपये से कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता की वजह से यह कार्य रुक गया था। केंद्र में नई सरकार के गठन और सियासी उठापटक के शांत होने के बाद अब नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन ने सदन के स्वीकृत प्रस्ताव का हवाला देते हुए नगर विकास विभाग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी थी।

विशेष सचिव ने सरकारी एजेंसी से कार्य कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद निगम ने आठ जून को यूपीनेडा के निदेशक को इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त करने और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने को पत्र लिखा है। यूपीनेडा की एक टीम ने प्लांट के लिए चिह्नित जमीन का निरीक्षण कर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि जुलाई में डीपीआर बन जाएगा और अगले एक साल में प्रोजेक्ट स्थापित हो जाएगा। सोलर मेगा प्लांट में हर महीने 25 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा, जिसे नेशनल ग्रिड में सप्लाई किया जाएगा। नेशनल ग्रिड को जितनी बिजली दी जाएगी, उतनी ही बिजली घटाकर नगर निगम और जलकल विभाग केस्को को भुगतान करेगा। शहरवासियों की प्यास बुझाने और सड़कें रोशन करने में ही हर महीने 9 करोड़ रुपये की बिजली खर्च होती है। सभी पंपिंग स्टेशन, जल शोधन संयंत्र व नलकूप के संचालन में हर महीने करीब 19000 किलोवॉट बिजली खर्च होती है। जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके त्रिपाठी ने बताया कि बिजली के मद में उनका विभाग केस्को को हर महीने करीब 4 करोड़ रुपये भुगतान करता है।

गंगा में डूबी बच्ची का मिला शव,दो दिन से गोताखोर कर रहे थे तलाश

उन्नाव (यूएनएस)। जनपद में बहन के साथ दो दिन पहले मवेशी चराने गई बच्ची अचानक गंगा नदी के गहरे पानी में डूब गई। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची की खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन अंधेरा होने से सफलता नहीं मिल सकी। बुधवार को भी बच्ची की गंगा में खोजबीन जारी रही। गुरुवार को गोताखोरों ने शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कटरी गदनपुर आहार गांव के मजरा भिखारी पुरवा निवासी सियाराम की 12 वर्षीय बेटी सिमरन अपनी बड़ी बहन मानसी और गांव के अन्य बच्चों के साथ बीते मंगलवार को मवेशी चराने गयी थी। इसी बीच सभी बच्चे गंगा नदी में नहाने लगे। अचानक सिमरन गहरे पानी में चली गयी। उसे बचाने का प्रयास बड़ी बहन व अन्य बच्चों ने किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद बच्चों ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

तीन जिलों से गुजरने वाली 93 किमी रिंग रोड पर करीब 13 टोल प्लाजा होंगे स्थापित

कानपुर देहात (यूएनएस)। कानपुर नगर, देहात व उन्नाव के बाहरी इलाकों से होकर गुजरने वाली रिंग रोड पर टोल टैक्स वसूली के लिए 13 टोल प्लाजा बनेंगे। पैकेज-1 में 03, पैकेज-2 में 04, पैकेज-3 में 04 व पैकेज-4 में 02 टोल प्लाजा होंगे। पैकेज-1 में 3 टोल प्लाजा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को स्वीकृति भी मिल गई है। जबकि अन्य पैकेजों के लिए टोल प्लाजा के स्थानों का चयन कर प्रस्ताव को भेजा गया है। मंत्रालय से अनुमति मिलते ही कार्य का विस्तार किया जाएगा। 93.20 किलोमीटर लंबी रिंग रोड को 5 पैकेज में विभाजित किया गया है। पैकेज-1 का निर्माण का तेजी से कराया जा रहा है, जबकि पैकेज 4 में 70 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 19.235 किमी लंबे पैकेज-3 का टेंडर ऋषिकेश की हिलवेज कंपनी को दिया गया है। पैकेज-2 (ए) व 2 (बी) में जल्द ही टेंडर प्रक्रिया का काम पूरा किया जाएगा। रिंग रोड में जितने किलोमीटर वाहन चलेगा, उतनी दूरी का ही टोल टैक्स चुकाना होगा। इसके लिए रिंग रोड पर प्रवेश व निकास के लिए 13 प्वाइंट बनाए जाएंगे, जो कानपुर नगर, देहात व उन्नाव जिले में होंगे। सभी जगहों पर वाहनों पर लगे फास्ट टैग को स्कैन करने के लिए अत्याधुनिक सेंसर लगाए जाएंगे पैकेज-1 में तीन स्थानों पर टोल बनाए जाएंगे। एनएच-2 हाईवे पर किसान नगर, शिवली रोड पर पुराशुबारा व पचौर गांव के बार्डर पर व मंधना के महाराजपुर गांव में टोल बनाए जाएंगे।

रेलवे ने वॉल बाउंड्री बनाने के लिए घरों को गिराया

उन्नाव (यूएनएस)। जनपद के गंगाघाट रेलवे स्टेशन का आदर्श स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया जा रहा है। इधर काम शुरू हो गया है। रेलवे की ओर से स्टेशन के चारों ओर दीवार बनवाई जानी है। जिसके बाद एक सौ अस्सी मीटर जमीन अधिग्रहित की जायेगी। जिससे राजीव नगर बस्ती का काफी हिस्सा जद में आया है। अब जेसीबी से घरों का गिराने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को आरपीएफ की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया है। ऐसे में भारी फोर्स देख कुछ ने खुद ही मकानों को खाली करने का काम शुरू कर दिया है। गंगाघाट रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। जहां कार्य करने के लिये बाहर से मजदूर भी आ गये हैं। उनके ठहरने के लिये अस्थाई क्वार्टर भी बनाये गये हैं। वहीं जल्द ही स्टेशन के कायाकल्प का कार्य एसएसई कार्य की देख रेख में होना है। शुरूआती दौर में प्लेटफार्म के दोनों ओर आड़े आने वाले पेड़ों को हटाया जायेगा। जिसके बाद प्लेटफार्म एक से राजीव नगर बस्ती की ओर 180 मीटर दूरी तक बाउंड्री वाल की जायेगी।

बाल निकुंज में विश्व पर्यावरण संवर्धन सप्ताह में वृक्षारोपण किया गया

लखनऊ। बाल निकुंज इंटर कॉलेज, मोहिबुल्लापुर सीतापुर रोड लखनऊ में दिनांक 05 जून से 12जून 2024 तक विश्व पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके दौरान स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, पर्यावरण संरक्षण चित्रकला प्रतियोगिता और पर्यावरण संवर्धन निबंध प्रतियोगिता आदि विभिन्न आयोजन किए गए।

विश्व पर्यावरण सप्ताह के समापन पर के पूर्व आज दिनांक 11 जून 2024 को नीम, अशोक व बेलपत्र आदि बड़े वृक्ष वाले पौधों का रोपण कर पर्यावरण संवर्धन व बचाव संगोष्ठी में शिक्षक, शिक्षिकाओं विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सुखी जीवन के प्रति जागरूक किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि श्री अजय खन्ना फील्ड जनरल मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, श्री मनोज सक्सेना क्षेत्रीय प्रबंधक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, श्री सुनील कुमार शर्मा मुख्य प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया और विशेष अतिथि श्री सौरभ सिंह शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलीगंज ने कॉलेज प्रबंध निदेशक श्री हृदय नारायण जायसवाल के साथ विद्यालय के नवीन प्रांगण में वृक्षा रोपण किया। मुख्य अतिथि ने सबको सचेत करते हुए बताया कि हम सभी को प्रतिवर्ष एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष हमारे जीवन के पांच तत्वों के साथ अहम भूमिका निभाते हैं। दूषित वातावरण हम सभी की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके प्रति हमें सदैव जागरूक बने रहने की नितांत आवश्यकता है।

स्लोगन लेखन प्रतियोगिता में कक्षा 10 की सबा आफरीन को प्रथम स्थान मिला। जिन्होंने अपने स्लोगन में दर्शाया कि सांस हो रही कम, आओ पेड़ लगे हम। के सचित्र वर्णन को सर्वाधिक सराहा गया। कक्षा 12 की दीपिका शर्मा को द्वितीय स्थान मिला जिन्होंने पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्लोगन के साथ सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया तथा कक्षा 10 की लक्ष्मी बर्मा ने मत फैलाओ अब प्रदूषण, पर्यावरण का करो संरक्षण। स्लोगन लिखकर सुंदर चित्रण के माध्यम से लोगों का मन मोह लिया और तृतीय पुरस्कार जीतने में सफल रही।

दूसरी तरफ बाल निकुंज इंटर कॉलेज बॉयज विंग के विद्यालय प्रांगण में ज्येष्ठ माह के तृतीय बड़े मंगल पर सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ-साथ कन्या भोज एवं विशाल भंडारे का आयोजन महाबली हनुमान जी की कृपा से देर शाम तक चलता रहा। मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ कॉलेज प्रबंध निदेशक एच एन? जायसवाल, कोऑर्डिनेटर सुधीर मिश्रा, प्रधानाचार्या श्रीमती रश्मि शुक्ला, प्रधानाचार्या श्रीमती भगवती भंडारी, उप प्रधानाचार्या सुश्री अनीता मौर्या, इंचार्जेस एवं शिक्षक गण उपस्थित रहे। आपसे अनुरोध है कि अपने सम्मानित समाचार पत्र में उपरोक्त समाचार को फोटो सहित प्रकाशित करने की कृपा करें।

महिला एएनएम से लूट का हुआ खुलासा, 3 गिरफ्तार

लखनऊ (यूएनएस)। मोहनलागंज इलाके में बीते 7 जून को महिला एएनएम घ्घ्के साथ लूट के मामले में पुलिस ने आज खुलासा किया है। घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर लूटेरे गिरफ्तार हुए है। डीसीपी ने लूटेरों को पकड़ने वाली टीम को 20 हजार रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की हैं।

पुलिस ने लूटेरों के पास से लूट के 3 मोबाइल, एक मंगलसूत्र, एक जोड़ी पायल सहित घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। मामले को लेकर डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने एडीसीपी शशांक सिंह और एसीपी मोहनलालगंज राधा रमण सिंह की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि नगराम के अपैया गांव में रहने वाली महिला राजकुमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से ड्यूटी खत्म कर ई-रिक्शा से घर वापस लौट रही थी। बिंदौआ मोड़ के आगे पहुंचने पर बाइक पर सवार 3 युवकों झपट्टा मारकर उसका पर्स लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद डीसीपी ने पुलिस की 4 टीमों लगाया। पुलिस टीम ने शेरपुर लवल तिराहे के पास से बाइक सवार तीन युवकों को दबोच लिया। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम उमेश साहू, सुमित मौर्य और रोहित साहू निवासी बाराबंकी बताया। मोहनलालगंज इंस्पेक्टर आलोक राव ने कहा, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि तेलीबाग के शनि मंदिर चौराहे पर लगने वाली लेबर मंडी में काम के लिए आए थे। काम न मिलने पर लूट की योजना बनाई।

आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के सेवा में वापसी के रास्ते बंद

लखनऊ (यूएनएस)। यूपी कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के दोबारा नौकरी में आने के प्रयासों पर ब्रेक लग गया है। फरवरी में उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया था। अब उन्होंने पुनः सेवा में आने के लिए नियुक्ति विभाग को आवेदन दिया था।

एक लाख रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो: युवा मंच

लखनऊ (यूएनएस)। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ से बिजली, सिंचाई, जल निगम समेत विभिन्न विभागों के तकनीकी संवर्ग में एक लाख रिक्त पदों को तत्काल भरने की मांग की गई। बताया गया कि करीब 40 हजार पद बिजली महकमे व 20 हजार पद सिंचाई विभाग में रिक्त पड़े हुए हैं जोकि सृजित पदों का करीब 50 फीसद है। जल निगम, नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग जैसे विभागों में तकनीशियन, जेई, एई, रेडियो आपरेटर के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। आईटीआई व पालीटेक्निक कालेजों में शिक्षकों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं।

तकनीकी संवर्ग के बेरोजगारों की अगुवाई कर रहे युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ई. राम बहादुर पटेल ने कहा कि लोक सभा चुनाव उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश जारी किया और विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। ऐसे में जिन विभागों के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले से उपलब्ध है उन पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। बताया कि सृजित पदों को तय मानक के अनुरूप बढ़ाने, सृजित पदों पर संविदा अथवा आऊटसोर्सिंग भर्ती पर कड़ाई से रोक लगाने, राजकीय आईटीआई व पालीटेक्निक कालेजों में निजीकरण पर रोक जैसे मुद्दों को भी उठाया जाएगा। कहा कि विगत 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है लेकिन पदों का सृजन उसके अनुरूप नहीं किया गया। उदाहरण देते हुए बताया कि पावर कारपोरेशन में एक अवर अभियंता के पास 2-3 सब स्टेशन का प्रभार आम बात है। यही हाल सभी विभागों में है।

पंचम तल से लेकर जिलों तक होगा प्रशासनिक फेरबदल

लखनऊ (यूएनएस)। यूपी में उच्च स्तरीय भारी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा। सूबे के चीफसेक्रेटरी का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। उनकी जगह पर कोई नया आला अधिकारी बैठाया जा सकता है।वही सूबाई सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव नियुक्त एवं कार्मिक जल्द ही केंद्र में प्रतिनियुक्त पर जाना है। उनको केंद्र में तैनाती के लिए राज्य सरकार के स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। राज्य सरकार ने कल ही तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आबकारी आयुक्त आदेश सिंह को आयुक्त राज्य कर का अतिरिक्त प्रभार दिया है। आयुक्त राज्यकर मिनिस्ती एस. छुट्टी पर हैं। धनंजय शुक्ला को विशेष सचिव नियुक्ति से अपर आयुक्त राज्य कर बना दिए गये। विशेष सचिव खनन विजय कुमार को विशेष सचिव नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। डा. मन्नान अख्तर को विशेष सचिव खनन बने है। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल और अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एनओसी भेज दी गई है। केंद्र में तैनाती मिलने के बाद जल्द ही दोनों आईएएस अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री ने की विभागीय समीक्षा

योजनायें,परियोजनायें समय से पूर्ण कर लोगों तक पहुंचाएं लाभः राजभर

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फएवं हज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायतीराज विभाग अलीगंज स्थित सभागार कक्ष में पंचायतीराज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पंचायती विभाग में चल रही योजनाओं परियोजनाओं एवं आगामी योजनाओं परियोजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने विभाग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी ली एवं भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने अभी तक किए गए बहुत-से विभागीय कार्यों की प्रशंसा की एवं विभाग द्वारा तय लक्ष्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत विभाग में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। पंचायतीराज मंत्री ने जिला पंचायतों की आय बढ़ाने पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पंचायतों के पास आय बढ़ाने के भरपूर संसाधन पंचायतों में उपलब्ध हैं। पंचायतें कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों की स्वयं भी प्रयास करें। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 जून तक कम से कम तीन जनपद का भ्रमण स्वयं करें, कहीं पर भी अनियमितता पाये जाने पर उसे दूर करने का प्रयास भी करें। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं बनायी जाएं उसका लाभ लोगों तक पहुंचे और धरातल पर लोग इसका अनुभव भी करें तभी योजनाएं सफल मानी जायेंगी। पंचायतों के अंतर्गत निर्माण कार्यों में एक ही ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा कार्य आवंटित किये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मुख्यालय के अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग करें एवं नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायें। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड के अधिकारी ग्राम पंचायतों के भ्रमण पर जाएं और भ्रमण की सूचना रजिस्टर पर भी अंकित करें, जिससे कि उनके द्वारा किये गए निरीक्षण की जानकारी हो सके। पंचायती राज मंत्री ने अधिकारियों से स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज की संकल्पना का प्रस्ताव बनाने का भी सुझाव दिया। दक्षिण भारत के राज्यों में स्मार्ट विलेज की संकल्पना पर कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मियों की ऑनलाइन उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। जीआईएस मॉनीटरिंग द्वारा उपस्थिति की जानकारी ली जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। जुलाई माह में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया जायेगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पंचायतीराज विभाग को नम्बर वन बनाना है। पंचायत भवन की बाउण्ड्री से लगी जमीनों, ग्राम पंचायत में स्थित तालाबों, पोखरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण कराया जाए। न केवल वृक्ष लगाएं बल्कि उसका संरक्षण एवं संवर्धन भी जरूरी है। वातावरण दिन प्रतिदिन घातक होता जा रहा है। हमें आने वाली पीढ़ियों के उज्वल भविष्य के लिए अधिक से अधिक संसाधनों को बचाकर रखना होगा।इस अवसर पर निदेशक पंचायतीराज अटल कुमार राय ने पंचायतीराज मंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक में अपर निदेशक पंचायतीराज राज कुमार, संयुक्त निदेशक पंचायतीराज आरएस चौधरी एवं एसके सिंह, उपनिदेशक पंचायतीराज परवीना चौधरी, एसएन सिंह, योगेन्द्र कटियार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजभवन पहुंचा पीसीएस-जे परीक्षा में कॉपी की अदला-बदली का मामला

प्रतियोगी छात्रों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर दर्ज कराई शिकायत

लखनऊ (यूएनएस)। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा- 2022 में कॉपी की अदला-बदली का मामला राजभवन पहुंच गया है। प्रतियोगी छात्रों ने राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को पत्र लिखकर मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली और अध्यक्ष की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राज्यपाल को लिखे पत्र में प्रतियोगी छात्रों ने समीक्षा अधिकारी आरओ एवं सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा-2023 में पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया है। प्रतियोगियों का कहना कि जिस तरह पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान परीक्षाओं में पेपर लीक और कॉपी की अदला-बदली के मामले सामने आए थे, वही स्थिति वर्तमान में है। आयोग अपनी पुरानी कार्यप्रणाली पर आ गया है।पीसीएस जे मुख्य परीक्षा-2022 के अभ्यर्थी श्रवण पांडेय का दावा है कि अंग्रेजी विषय की कॉपी पर उसकी हैंडराइटिंग नहीं है यानि कॉपी बदली गई है। इस दावे की अभी पुष्टि नहीं हुई है और आयोग हकीकत का पता लगाने केलिए पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की 18 हजार से अधिक कॉपियों की जांच करा रहा है। कॉपियों में अंकित फेक मास्टरकोड को डिकोड किया जा रहा है।आयोग की ओर से उठाए गए इस कदम पर भी प्रतियोगियों ने सवाल उठाए हैं और पूछा कि जांच के दौरान कॉपियों में फिर से कोई हेरफेर न हो, इसकी क्या गारंटी है। छात्रों ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि आरओ,एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में आयोग ने पेपर लीक की घटना से साफइनकार कर दिया था। अभ्यर्थियों के आंदोलन करने पर शासन ने सीधे हस्तक्षेप पर परीक्षा निरस्त की थी, वरना आयोग तो मनमानी पर उतारू था। पीसीएस जे मुख्य परीक्षा में कॉपी की अदला-बदली का मामला सामने आने पर अभ्यर्थी को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, तब आयोग ने कॉपियों की जांच शुरू कराई। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का आरोप है कि आयोग में अभ्यर्थियों की सीधे तौर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसी वजह से आयोग अभ्यर्थियों के बीच अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। ऐसे में आयोग की कार्यप्रणाली की उच्च स्तरीय जांच होनी ही चाहिए।

आउटसोर्सिंग से भर्ती के पत्र पर बवाल

लखनऊ (यूएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ पदों के लिए आउटसोर्सिंग भर्ती करने वाली है। यह जानकारी जब एक पत्र के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कुछ वक्त बाद पत्र को निरस्त कर दिया गया तो हड़कंप मच गया।सवाल उठे और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया शुरू हो गई।यूपी सीएम योगी इस मामले को लेकर खासे नाराज हैं।कहते हैं कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस मामले को लेकर सफाई दी है और कहा है कि पत्र त्रुटिवश जारी हो गया था। डीजीपी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से पहले से लिया जा रहा है लेकिन गलती से यह मिनिस्टीरियल स्टाफके नाम से जारी हो गया। इसे निरस्त कर दिया गया है और ऐसा आदेश अमल में नहीं लाया जा रहा है। पत्र पुलिस कमिश्नर, आईजी रेंज, एडीजी जोन, पुलिस अधीक्षकों के नाम जारी हुआ था जिसमें लिखा था कि पुलिस विभाग आउटसोर्सिंग के जरिए कई पद भरने वाला है। जब पत्र जारी होकर निरस्त हुआ तो युवाओं में खासा असंतोष बना और सोशल मीडिया पर लिखा गया कि अगर पत्र गलती से जारी हुआतो कार्रवाई क्यों नहीं ?

जनवीणा

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सुधा द्विवेदी द्वारा प्रिंट आर्ट आफसेट, 33 कैण्ट रोड, लखनऊ से मुद्रित तथा प्रथम तल, कैपिटल सिनेमा बिल्डिंग, विधानसभा मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

सम्पादक- सुधा द्विवेदी
कार्यकारी सम्पादक
डॉ. एस.के.गोपाल
प्रबंध सम्पादक
होमेन्द्र कुमार मिश्र
क्रिएटिव एडिटर
नैमिष सोनी
विशेष संवाददाता
सौरभ कुमार पाण्डेय
संवाददाता
जादूगर सुरेश कुमार
सम्पर्क : 9451532641, 8765919255
ईमेल :janveenanews@gmail.com
RNI No. UPHIN/2011/43668
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

मायावती ने कुवैत में भारतीयों की मौत पर जताया दुख

लखनऊ (यूएनएस)। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कुवैत अग्निकांड हादसे में भारतीयों की मौत पर दुख जताया तथा केंद्र सरकार से पीड़ितों के परिजन की पूरी मदद करने की मांग की है। मायावती ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कुवैत अग्निकांड हादसे में, 41 भारतीयों की मौत होना अत्यंत दुःखद है। मरने वालों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है तथा घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करती हूं। केन्द्र सरकार, उनके परिवार वालों की पूरी मदद करें। गौरतलब है कि बुधवार को कुवैत में मंगाफ शहर की एक इमारत में आग लगने से करीब 40 भारतीयों सहित 49 विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई और 50 अन्य लोग घायल हो गए।

इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों में से अब तक नागरिकों की पहचान हो सकी है, जो केरल के रहने वाले थे। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। अग्निकांड में मरने वाले ज्यादातर केरल और तमिलनाडु के लोग हैं। इस हादसे की खबर के बाद दोनों राज्यों के परिवारों में गम का माहौल है। प्रधानमंत्री ने कुवैत में आग की घटना से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की है।